दिल्ली, उ0प्र0, हरियाणा, पंजाब, गुजरात एवं राजस्थान में प्रसारित।

गुरुकृपा दर्पण

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

UTTHIN/2022/85670

डाक सं० UA/DO/DON/02/2024-2026

वर्ष : 04 | अंक : 36 | हरिद्वार | शनिवार, 27 सितम्बर, 2025 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 4

शहीद सम्मान यात्रा उन अमर बलिदानियों को समर्पित है, जिनकी शौर्यगाथा और बलिदान सदैव हमें प्रेरणा देते रहेंगे : मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को शहीद राईफल मैन नरेश कुमार के गुजराड़ा मानसिंह सहस्त्रधारा रोड़ स्थित आवास से शहीद सम्मान यात्रा 2 का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने इससे पहले शहीद राईफलमैन नरेश कुमार के चित्र पर माल्यार्पण के साथ ही शहीद स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद नरेश कुमार के परिजनों से भेंट कर उनके आंगन की मिट्टी का भी संग्रहण किया। उन्होंने शहीद के परिजनों को शहीद सम्मान समारोह में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा देहरादून के गुनियाल गांव मे शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण कराया गया है जिसमें प्रदेश के सभी शहीद सैनिकों के घर-आँगन की पवित्र

मिट्टी स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहीद सम्मान यात्रा उन अमर बलिदानियों को समर्पित है, जिनकी शौर्यगाथा और बलिदान सदैव हमें प्रेरणा देते रहेंगे। हमारे शहीदों ने अपना आज हमारे कल के लिए न्यौछावर किया है। उनके त्याग और पराक्रम के कारण ही हम सब सुरक्षित और स्वतंत्र हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व का अवसर है, जब हम उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया। शहीदों का बलिदान हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक मूल्य त्याग, सेवा और समर्पण में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में वर्ष 2018 से अब तक 28 शहीद आश्रितों को उनकी योग्यता अनुसार नियुक्ति दी जा चुकी है और 13 की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। शहीदों के परिजनों को एकमुश्त अनुग्रह अनुदान जो पहले 10 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है। इसी प्रकार उत्तराखण्ड़ के परमवीर चक्र अलंकृत सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दी जाने वाली राशि 50 लाख रूपये से बढाकर अब 1.50 करोड़ रूपये कर दी गयी है। उत्तराखण्ड़ देश का पहला राज्य है जहां पूर्व सैनिकों को ब्लॉक प्रतिनिधि नियुक्त मानदेय प्रदान किया है वर्तमान में यह मानदेय 8,000 रुपये प्रतिमाह है, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देहरादून में निर्मित हो रहे सैन्य धाम निर्माण से पूर्व प्रदेश के 1734 अमर बलिदानियों के आंगन की पवित्र मिट्टी सैन्य धाम लाई जा चुकी है। प्रदेश में शहीदों के सम्मान की परंपरा वर्ष 2021 से प्रारम्भ हुई। उस वर्ष जिला एवं राज्य स्तर पर शहीद सम्मान समारोह आयोजित किए गए और शहीद परिजनों को ताम्रपत्र भेंट किए गए। वर्ष 2021 में कतिपय कारणों से 39 शहीद सैनिकों के घर-आँगन की मिट्टी संग्रहित नहीं हो सकी थी। इसके पश्चात 2021 से 2025 के बीच प्रदेश के 32 और वीर सैनिक मातृभूमि पर बलिदान हुए।

नगर निगम अल्मोड़ा के तत्वावधान में लोक कल्याण मेले का आयोजन

अल्मोड़ा। नगर निगम अल्मोड़ा के तत्वावधान में सोमवार को जिला सहकारी बैंक सभागार में लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर पी.एम. स्वनिधि पुनर्गठित योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रभारी सहायक नगर आयुक्त लक्ष्मण सिंह भंडारी ने बताया कि मेले का आयोजन सिटी मिशन मैनेजर शांता गुरुरानी और प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेषज्ञ रमेश जोशी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम के दौरान %स्वच्छता ही सेवा 225% के अंतर्गत स्वच्छता शपथ ग्रहण भी कराया गया। सिटी मिशन मैनेजर ने कहा कि पी.एम. स्वनिधि पुनर्गठित योजना का उद्देश्य सड़क पर काम करने वाले विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाना, आजीविका संवर्धन, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण के साथ डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत नए आवेदनों को भरवाने, पहले से स्वीकृत ऋणों का वितरण कराने, निरस्त आवेदनों को पुन: स्वीकृत कराने और डिजिटल रूप से निष्क्रिय लाभार्थियों को यूपीआई आईडी व क्यूआर कोड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही %स्वनिधि से समृद्धि योजना% के तहत लाभार्थियों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जोड़ने की जानकारी दी गई। रमेश जोशी ने %अंगीकार 225 व्यापक आउटरीच अभियान% के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य हर पात्र परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराना, आवेदनों का सत्यापन करना, स्वीकृत घरों का शीघ्र निर्माण कराना और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आवास योजना से जोड़ना है।

गुरुकृपा दर्पण (राष्ट्रीय समाचार पत्र) को आवश्यकता है उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लिए ब्यूरो चीफ, कैमरा मैन, संवादाताओं की। सम्पर्क करें – 9410731129, 9548880101

पीएचसी इमलीखेड़ा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर ने 221 लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार

हरिद्वार। जनपद वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करने के उद्देश्य से शासन के निर्देशों के अनुपालन में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर पखवाड़े आयोजित किए जा रहे है जिसके उद्देश्य अधिक से अधिक जनपद वासियों का नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इमलीखेड़ा ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ अध्यक्ष नगर पंचायत इमलीखेड़ा मनोज कुमार सैनी ने किया। स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम के तहत लगाए जा रहे स्वास्थ्य शिविरो के माध्यम से क्षेत्रवासियों का नि:शुल्क ईलाज किया जा रहा है,जिसके लिए उन्होंने सभी से आयोजित हो रहे स्वास्थ्य शिविरो का लाभ लेने का आवाह्न किया है,उन्होंने क्षेत्रवासियों से उपेक्षा की है कि आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविरों का अधिक से अधिक लोगों को शिविर में पहुंच कर स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आर के सिंह ने अवगत कराया है कि आज आयोजित किए गए स्वास्थ्य शिविर में 221 लोगों का पंजीकरण एवं उपचार किया गया है जिसमें जनरल सर्जरी के 38, बालरोग के 21,दंत चिकित्सा के 13, प्रसूति एवं स्त्री रोग के 52, , बीपी 82, शुगर 67, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग 28, एएनसी 17, बलगम जांच के सैंपल 27, तथा 15 लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए एवं 64 लोगों के एक्सरे किए गए तथा 18 दिव्यांग प्रमाण पत्र भी लाभार्थियों को वितरित किए गए। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुड़की डॉ रमेश कुंवर, प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ राव अकरम,डॉ डिल्ली रमन, डॉ राजकुमार ,डॉ राजीव रंजन तिवारी,डॉ राजकेश पांडे,डॉ श्रेयांश सैनी,डॉ पृथा चौधरी,डॉ शिखा सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी एवं विभिन्न क्षेत्रों से आए क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

सम्पादकीय

उच्चतम शिखर

सम्पादक – देवेन्द्र जौहरी

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है, और अगले पांच साल में इस बाजार में पहले नंबर पर आने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। गडकरी ने अंतरराष्ट्रीय वैल्यू शिखर सम्मेलन, 2025 में उस रोडमैप का ब्योरा भी दिया जिसके तहत भारत को ऑटोमोबाइल विनिर्माण, हरित गतिशीलता और बुनियादी ढांचे के नवाचार के लिए दुनिया के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने की महत्त्वाकांक्षी योजना है। गडकरी के अनुसार सभी प्रमुख वैंकि ऑटोमोबाइल ब्रांड अब भारत में मौजूद हैं। इन ब्रांडों का ध्यान अब असेंबलिंग करने से हट कर भारत से दुनिया भर में वाहनों के निर्यात पर केंद्रित हो गया है। देखा जाए तो अकेले भारत का दोपहिया वाहन उद्योग अपने उत्पादन का आधे से ज्यादा निर्यात करता है। प्रदूषण मुक्त परिवहन के मामले में भी भारत की अग्रणी भूमिका बनी हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन ईधन और वैकल्पिक ईधनों में भारत खूब प्रगति कर रहा है। हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च कर ही चुका है, और अनेक मागरे पर इसकी पायलट परियोजनाएं चल रही हैं। भारत का लक्ष्य हरित परिवहन में दुनिया का नेतृत्व करना है। प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और रिलायंस तथा इंडियन ऑयल जैसी तेल कंपनियों के सहयोग से सरकार ने हाइड्रोजन उत्पादन के बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए भारी-भरकम अनुदान दिया है।

जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधिकारी ने चकराता के मोहना गांव में किया 'आदि सेवा केंद्र का उद्घाटन

देहरादून। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ''आदि कर्मयोगी अभियान'' के अन्तर्गत जनपद के ०5 विकासखण्डों के 81 गांवों का चयन किया गया है। इसके अन्तर्गत चयनित विकासखण्ड चकराता के मोहना गांव में जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार से स० अनुभाग अधिकारी रवि शेखर ने गांव का भ्रमण किया। जनजाति कार्य मंत्रालय के अधिकारी ने गांव में ''आदि सेवा केन्द्र'' का उद्घाटन किया गया और ग्रामीणों से वार्ता की। श्री रवि द्वारा ग्राम वासियों को पलायन रोकने हेतु कृषि एवं होम स्टे से सम्बन्धित योजनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ताकि गांव में स्वरोजगार बढे और पलायन को रोका जा सके। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान मनीषा, डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर आदि कर्म योगी अभियान अनिल कुमार, ब्लाक मास्टर ट्रेनर खजान सिंह एवं अन्य क्षेत्रीय कार्मिक उपस्थित रहे। ग्राम वासियों ने बडी संख्या में इस अभियान में प्रतिभाग किया।

दून बौद्ध समिति के प्रतिनिधिमण्डल ने की राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से गुरुवार को दून बौद्ध समिति के प्रतिनिधिमण्डल ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के साथ सामाजिक, शैक्षणिक एवं समसामयिक विषयों पर सार्थक संवाद किया। उन्होंने समिति द्वारा शिक्षा और समाजहित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार और नैतिक मूल्यों का समावेश समाज के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यपाल को अपने शिक्षण संस्थानों की गतिविधियों, सामाजिक पहलों तथा इनसे जुड़ी चुनौतियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने उन्हें समाज और शिक्षा क्षेत्र में निरंतर सकारात्मक योगदान हेतु प्रोत्साहित किया और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

यूकेएसएसएससी परीक्षा नकल के मुख्य आरोपित की संपत्ति पर चला बुलडोजर

हरिद्वार। यूकेएसएसएससी परीक्षा नकल के मुख्य आरोपित खालिद की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं खालिद ने अपने परिवार ही नहीं, सुल्तानपुर कस्बे का नाम भी डुबो दिया। जबकि उसके परिवार की गिनती प्रतिष्ठित परिवारों में होती थी। नकल मामले में फंसने के बाद उसकी दो बहनों की शादी टूटने की चर्चाएं भी बनी हुई है। सुल्तानपुर कस्बे में हर तरफ खालिद की चर्चाएं हैं। लोग उसकी करतूत पर शर्मिंदा हैं। लक्सर का सुल्तानपुर कस्बा पिछले चार दिन से पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य आरोपित खालिद मलिक भले ही अक्सर सुल्तानपुर से बाहर रहता आ रहा है, मगर उसका जुड़ाव इसी कस्बे से है। ऐसा बताया गया है कि खालिद के दादा सरकारी सेवा में थे और लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। मगर खालिद के कारनामे से परिवार को बदनामी झेलनी पड़ी है। कस्बे में चाय की दुकान, सैलून, बस अड्डे तक हर जगह आमजन की जुबान पर भी यही चर्चाएं हैं कि एक व्यक्ति की गलती से पूरे कस्बे का नाम खराब हो रहा है। खालिद चार बहनों का भाई है। उसकी एक बहन सबिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी बहन हीना मुकदमे में नामजद है। जबकि बाकी दो बहनों से पुलिस ने रायपुर थाने में घंटों पूछताछ की। इससे रिश्तेदार भी दुखी हैं। मेहनत करता तो नकल की जरूरत न पड़ती= एक रिश्तेदार ने बताया कि घर के बेटे की करतूत के चलते महिलाओं को भी परेशानी भरनी पड़ रही है। खालिद ने जितनी तिकड़म पेपर में नकल करने में लगाई है, यदि उतनी ही मेहनत कर लेता तो नकल की जरूरत न पड़ती।

नागरिक सेवाओं में करियर अवसर विषय पर कार्यशाला का आयोजन

हरिद्वार। प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान वाजीराम एंड रवि की टीम ने नागरिक सेवाओं में करियर अवसर विषय पर कार्यशाला का आयोजन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय, हरिद्वार में किया। कुलपति प्रो. हेमलता के. ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने हमेशा अपने विद्यार्थियों को शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ मूल्य आधारित शिक्षा देने का प्रयास किया है। यह कार्यशाला न केवल नागरिक सेवाओं के महत्व को रेखांकित करती है, बल्कि छात्रों को यह अवसर भी देती है कि वे समझ सकें कि अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग समाज के उत्थान के लिए कैसे किया जा सकता है। कुलसचिव प्रो. विपुल शर्मा ने कहा कि नागरिक सेवा में करियर बनाना केवल व्यक्तिगत उपलब्धि ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा करने का माध्यम भी है। इस प्रकार के सत्र हमारे छात्रों को आत्मविश्वासी और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इस सत्र का संचालन संस्थान के विशेषज्ञ समर और आकाश के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी तथा सीएओसी इंचार्ज डॉ. सुयश भारद्वाज, जिन्होंने कार्यक्रम का समन्वयन किया, ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को नागरिक सेवाओं की तैयारी, रणनीति और उपलब्ध अवसरों के बारे में प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्रदान करना है। कुल 65 विद्यार्थियों ने इस कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया और सत्र के दौरान अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। विभागाध्यक्ष प्रो. मयंक अग्रवाल ने कहा कि हमारे इंजीनियरिंग के छात्र केवल तकनीकी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रशासन और नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार की कार्यशालाएं उन्हें व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं और उन्हें नागरिक सेवाओं जैसी प्रतिष्ठित करियर संभावनाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में दारोगा समेत दो पुलिसकर्मी निलंबित

हरिद्वार। यूकेएसएसएससी (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) पेपर लीक मामले में एक तरफ जहां पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है तो वहीं दूसरी ओर उन अधिकारियों पर भी गाज गिर रही है, जिनकी लापरवाही के वजह से पेपर लीक हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन और सेक्टर मजिस्ट्रेट सस्पेंड होने के बाद अब दारोगा समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। दोनों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादरपुर जट हरिद्वार पर थी। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल की तरफ से दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी हैं। दोनों पुलिसकर्मियों पर परीक्षा केंद्र में ड्यूटी के दौरान संवेदनशीलता और सतर्कता न बरतने का आरोप है। हरिद्वार एसएसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों की इस लापरवाही को गंभीरता से लिया और दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश पारित किया है। एसएसपी डोबाल ने साफ कहा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

देवेन्द्र जौहरी
सहसम्पादक
जतिन शर्मा
सहसम्पादक
विक्रान्त शर्मा
कानूनी सलाहकार
जसमहिन्द्र सिंह एडवोकेट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच

डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम

देश लोक प्रशासन में सुधार के अभूतपूर्व प्रयास कर रहा है। अब न केवल अधिकारियों के प्रशिक्षण के तरीके बदल रहे हैं, बल्कि उनकी सेवा के मायनों में भी बदलाव आ रहा है। मिशन कर्मयोगी-लोक सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस बदलाव में इंजन की भूमिका निभा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच झलकती है। 25 वर्षों से अधिक समय तक सरकार चलाने और पांच दशकों से अधिक सार्वजनिक जीवन का अनुभव रखने वाले मोदी, व्यवस्थाओं के प्रति एक संचालक जैसी समझ, जड़ आदतों के प्रति एक सुधारक जैसी अधीरता, और ध्रुव तारे की तरह स्पष्ट-नागरिक-प्रथम, विकसित भारत के उद्देश्य को सामने रखते हैं। मिशन कर्मयोगी की खासियत यह है कि यह केवल दिखावे भर के लिए मानव संसाधन सुधार नहीं है। यह देश की लोक सेवाओं की मूल्य-आधारित परिवर्तनकारी पुनर्रचना है और इसका मुख्य ध्यान प्रदर्शन पर है। यह कार्यक्रम तीन निर्णायक बदलावों को संहिताबद्ध करता है- पहला बदलाव; सरकारी अधिकारियों की मानिसकता में बदलाव है, यानी स्वयं को कर्मचारी मानने से लेकर कर्मयोगी मानने तक का सफर है। दूसरा बदलाव; कार्यस्थल में बदलाव है, इसमें प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी सौंपने से लेकर प्रणालीगत प्रदर्शन बाधाओं का निदान और उन्हें दूर करने तक का बदलाव शामिल है। तीसरा बदलाव; सार्वजनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और उससे जुड़ी क्षमता निर्माण प्रणाली को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित बनाना है। यह संरचना स्पष्ट रूप से मोदी के इक्कीसवीं सदी के शासन की मांगों के दूरदर्शी ढांचे से उभर कर सामने आई है। यह जीवंत नेतृत्व का परिणाम है। मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी ने एक समग्र सरकारी संस्कृति को बढ़ावा दिया-अलग-अलग क्षेत्रों में अलगाव को खत्म किया, मंत्रियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बहस पर बल दिया, और फाइलों को आगे बढ़ाने की बजाय सिस्टम समाधानों को प्राथमिकता दी। यह भावना महामारी के दौरान दिखाई दी, जब सरकार, उद्योग, नागरिक समाज और नागरिक स्वयंसेवकों के सभी स्तरों पर %टीम इंडिया' एक साझेदारी मॉडल के रूप में आगे बढ़ी। उन्होंने नेतृत्व की आदतों को संरचनाओं में भी ढाला। जो चिंतन शिविर-आवासीय, पदानुक्रम-समतल विचार-मंथन सत्र-गुजरात में शुरू किए गए थे वे अब केंद्र सरकार की कार्यपुस्तिका का हिस्सा हैं। निरंतर सीखने पर उनका बल व्यक्तिगत है। अपने ज्ञान और कौशल का निरंतर विस्तार करने के अलावा, वे यह भी जांचने के लिए जाने जाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी आईजीओटी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। संस्थागत स्मृति के साथ उनके व्यवहार में बहुत समावेशीता है। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, उन्होंने मंत्रियों से दशकों तक एक तरह से व्यवस्था से भली-भांति परिचित अपने सहायकों और अनुभाग अधिकारियों से सीखने का आग्रह किया। जमीनी स्तर पर, सुधार की रीढ़ उद्देश्यपूर्ण तकनीक है। आईजीओटी-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म एक व्यापक, कभी भी और कहीं भी सीखने का ईको सिस्टम है। इसमें 3` से ज्यादा स्व-प्रगति पाठ्यक्रम हैं जो सभी के लिए सुलभ हैं और सीखने को लोकतंत्रात्मक बनाते हैं। मिशन कर्मयोगी प्राचीन सभ्यतागत ज्ञान को आधुनिक शासन-कला के साथ जोड़ता है- विकास, गर्व, कर्तव्य और एकता जैसे संकल्पों के साथ-साथ स्वाध्याय, सहकार्यता, राजकर्म और स्वधर्म (नागरिकों पर ध्यान) जैसे व्यक्तिगत गुणों को भी समाहित करता है। यह कोई पुरानी यादें नहीं हैं; यह उच्च तकनीक युग के लिए एक व्यावहारिक नैतिकता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि योग्यता चरित्र में समाहित हो। नागरिक-केंद्रितता-जनभागीदारी-दूसरा स्तंभ है। प्रधानमंत्री मोदी बार-बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि प्रत्येक सार्वजनिक निर्णय के केंद्र में नागरिक होने चाहिए। यही उनका शासन मंत्र है। व्यवहार में नागरिक सहभागिता दोतरफा समझौता बन जाती है। नीति और क्रियान्वयन में लोगों की भागीदारी होती है और अधिकारी अंतिम छोर पर खड़े अंतिम नागरिक की सेवा के लिए तैयार होते हैं। मिशन कर्मयोगी इस समझौते के लिए मानसिकता और तरीके विकसित करने का राज्य का साधन है। आत्मनिर्भरता इसकी पूरक है। यह एकाकीपन नहीं है; यह खुलेपन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से प्रेरित क्षमता और आत्मविश्वास है। यही दृष्टिकोण क्षमता निर्माण के प्रयासों और माईगव जैसे प्लेटफॉर्म के व्यापक प्रसार में भी दिखाई देता है, जो नागरिकों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, बल्कि सह-निर्माता बनाता है। यह कथा भारत के सभ्यतागत लोकाचार में निहित है-और संस्थानों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के युग में फलने-फूलने के लिए तैयार करती है। सीधे शब्दों में कहें तो, मिशन कर्मयोगी एक दूरदर्शी विचार को एक व्यवस्था में बदल देता है। यह प्रधानमंत्री मोदी के शासन के लंबे दायरे-उनकी सीमाओं को तोड़ने की सहज प्रवृत्ति, तकनीक के साथ उनका सहज व्यवहार, संस्थागत स्मृति के प्रति उनके सम्मान और उनकी नैतिक शब्दावली-को एक दोहराए जाने योग्य संचालन मॉडल में बदल देता है- भूमिका-आधारित मानव संसाधन; निरंतर, डिजिटल शिक्षा; नागरिक भागीदारी; और सभ्यता पर आधारित नैतिकता इसमें समाहित हैं। इस तरह आप किसी देश को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। अगर भारत इसी राह पर चलता रहा, तो इसका फायदा सिर्फ तेज गति से आगे बढ़ने वाली काम की फाइलों और व्यवस्थित संगठनात्मक चार्ट में ही नहीं, बल्कि भरोसे में भी दिखेगा। नागरिक एक ऐसी सरकार का अनुभव करेंगे जो सुनती है, सीखती है और काम करती है। यही प्रधानमंत्री मोदी के दांव का मूल है। और यही वजह है कि मिशन कर्मयोगी, हाल के दशकों के किसी भी प्रशासनिक सुधार से ज्यादा, अपने असली रूप में देखा जाना चाहिए। यह लोगों की सेवा करने वाले लोगों में एक पीढ़ीगत निवेश है और इसे एक ऐसे नेता ने तैयार किया है जिसने अपना जीवन लोगों की सेवा में ही लगा दिया है।

स्वच्छ शौचालय अभियान: स्वच्छता की ओर बदलती सोच और बढ़ते कदम

भारत में स्वच्छता की चर्चा जब भी होती है, तो केवल कचरा या गंदगी की सफाई ही नहीं बल्कि शौचालयों की उपलब्धता और उनका नियमित उपयोग भी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आती है। लंबे समय तक खुले में शौच की समस्या देश की छवि और स्वास्थ्य दोनों के लिए बाधा बनी रही। वर्ष 214 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया, तब इस समस्या को दूर करने की दिशा में व्यापक प्रयास शुरू हुए। घर-घर शौचालय बनने लगे, शहरों और कस्बों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ और धीरे-धीरे समाज में यह संदेश घर करने लगा कि स्वच्छता केवल सरकार का कार्य नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी हैइसी सोच को आगे बढ़ाते हुए क्लीन टॉयलेट अभियान की शुरुआत हुई, जिसकी थीम है - स्वच्छ शौचालय हमारी जिम्मेदारी। इस अभियान का मकसद केवल शौचालय बनाना नहीं, बल्कि उन्हें स्वच्छ, सुरक्षित और उपयोगी बनाए रखना है। क्योंकि यह बार-बार देखा गया कि शौचालय बन जाने के बाद भी उनका रखरखाव न होने से लोग उन्हें छोड़कर फिर खुले में शौच करने लगते थे। इसलिए इस अभियान ने ध्यान केंद्रित किया नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, सफाई मित्रों और स्थानीय निकायों के सहयोग तथा सामुदायिक जिम्मेदारी पर। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर क्लीन टॉयलेट अभियान का भी अग्रणी उदाहरण है। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर नगर निगम ने शौचालय सुपर स्पॉट कैंपेन आयोजित किया। इस अनोखे अभियान में नागरिकों को प्रोत्साहित किया गया कि वे सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करें और वहां पर अपनी उपस्थिति को तस्वीर के माध्यम से दर्ज करें। नतीजा यह हुआ कि शहर के सात सौ से अधिक शौचालयों पर एक लाख से ज्यादा लोगों ने जाकर सेल्फी ली और उसे ऑनलाइन अपलोड किया। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है बल्कि यह दर्शाता है कि इंदौर के नागरिक स्वच्छता को गर्व और जिम्मेदारी दोनों मानते हैं। खास बात यह रही कि अभियान की शुरुआत के केवल तीन घंटे के भीतर ही तीस हजार से अधिक तस्वीरें अपलोड हो चुकी थीं। सुबह पांच बजे से आठ बजे तक का यह दृश्य बताता है कि नागरिक कितनी तत्परता और जागरूकता के साथ इसमें भाग ले रहे थे। इंदौर का यह प्रयोग न केवल पूरे देश के लिए प्रेरणा है बल्कि यह संदेश भी देता है कि यदि जनता प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के अशोक नगर इलाके की कहानी बताती है कि बदलाव के लिए बड़े साधनों की नहीं बल्कि छोटे प्रयासों की आवश्यकता होती है। नगर निगम ने बबलू महतो को एक सार्वजनिक सुविधा केंद्र की देखभाल की जिम्मेदारी दी। यह स्थान पहले असामाजिक तत्वों का अड्डा माना जाता था। लोग वहां जाने से डरते थे और शौचालय लगभग बेकार पड़ा था। लेकिन बबलू महतो ने अपने परिवार के सहयोग से इस स्थान का कायाकल्प कर दिया। उन्होंने न केवल शौचालय और स्नानघर की नियमित सफाई सुनिश्चित की बल्कि आसपास का वातावरण भी पूरी तरह बदल डाला। धीरे-धीरे यह स्थान लोगों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ सार्वजनिक स्थल बन गया। उनकी पत्नी अनीता और पूरा परिवार इस जिम्मेदारी को निभाने में बराबर का योगदान देता है। आज यह सुविधा केंद्र इलाके के लोगों के लिए वरदान बन चुका है। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि यदि जिम्मेदारी का भाव हो तो कोई भी व्यक्ति समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। कोरबा जिले के प्रभास शाही ने अपनी सतत मेहनत और सेवा से स्वच्छता अभियान को एक नया आयाम दिया। वे पिछले दस वर्षों से शहर के नए बस स्टैंड और अन्य इलाकों में बने तेईस सार्वजनिक शौचालयों की देखभाल कर रहे हैं। उनकी सोच केवल सफाई तक सीमित नहीं रही। उन्होंने इन शौचालयों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया। महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर, इंसीनेरेटर और बेबी फीडिंग रूम जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराईं। यह सब बिना किसी बड़े प्रचार-प्रसार के हुआ, लेकिन इसका असर पूरे शहर पर पड़ा। प्रभास शाही की मेहनत का ही परिणाम है कि कोरबा शहर खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हुआ और ह्यष्ठस्न++ का दर्जा प्राप्त कर सका। यह उपलब्धि बताती है कि व्यक्तिगत प्रयास भी सामूहिक सफलता में बदल सकते हैं। क्लीन टॉयलेट अभियान केवल सफाई का सवाल नहीं है, यह स्वास्थ्य और गरिमा दोनों से जुड़ा हुआ है। खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय का होना उनकी गरिमा और आत्मसम्मान का सवाल है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लंबे समय तक महिलाओं को अंधेरे में खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे न केवल उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता था बल्कि सुरक्षा की समस्या भी बनी रहती थी। आज जब सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का जाल बिछाया गया है, तो जिम्मेदारी यह बनती है कि उनकी स्वच्छता और उपयोगिता बनी रहे। यदि वे गंदे या अनुपयोगी होंगे तो लोग फिर से पुराने तरीकों की ओर लौट सकते हैं। इसलिए क्लीन टॉयलेट अभियान का संदेश यह है कि निर्माण के साथ-साथ रखरखाव भी उतना ही जरूरी है। हालांकि इस अभियान की सफलता के बावजूद कई चुनौतियाँ सामने हैं। कई शहरों में शौचालय तो बन जाते हैं लेकिन उनका नियमित रखरखाव नहीं हो पाता। पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएँ न होने से उनका उपयोग कठिन हो जाता है। कई बार नागरिक भी लापरवाही बरतते हैं और शौचालयों को गंदा छोड़ देते हैं। इन समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब नागरिक, प्रशासन और सफाई मित्र मिलकर काम करें। एक ओर स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि शौचालयों की सफाई और मरम्मत नियमित रूप से हो, वहीं नागरिकों को भी इन्हें अपनी संपत्ति मानकर संभालना होगा। जागरूकता अभियानों, जन सहभागिता और तकनीक के उपयोग से इस दिशा में और सुधार किया जा सकता हैक्लीन टॉयलेट अभियान की सबसे बड़ी ताकत है जनभागीदारी। जब लोग इसमें जुड़ते हैं तो यह केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि एक आंदोलन बन जाता है। इंदौर, बिलासपुर और कोरबा जैसे उदाहरण यही साबित करते हैं। इंदौर में नागरिकों का उत्साह, बबलू महतो और प्रभास शाही जैसे व्यक्तियों की निष्ठा और प्रशासन का सहयोग मिलकर इसे सफल बनाता है। यही कारण है कि यह अभियान अब पूरे देश में तेजी से फैल रहा है।

मुख्य सचिव अध्यक्षता में हुई नंदादेवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली नंदादेवी राजजात यात्रा के तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी चमोली को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभागों और स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संपूर्ण यात्रा को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शीघ्र तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रा की ऐतिहासिकता, विशिष्टता और मौलिकता से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। उन्होंने इसकी डॉक्यूमेंट्री भी तैयार किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण बहुत से यात्रा मार्ग और पड़ावों की स्थिति की जानकारी के लिए मार्गों और पड़ावों की रेकी करायी जाए। मार्गों एवं पड़ावों को दुरूस्त कराए जाने के लिए तत्काल कार्यवाही शुरू की जाए। उन्होंने टैन्ट आदि की व्यवस्था के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। मुख्य सचिव ने नंदादेवी राजजात यात्रा के लिए कराए जाने वाले सभी स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति के कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अनिवार्य रूप से कराए जाने वाले बड़े कार्यों को प्राथमिकता में लेते हुए तत्काल शुरू कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक यात्रा पड़ाव एवं संपूर्ण यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य अधिकारियों, दवाओं, पोर्टेबल ऑक्सीजन एवं स्वास्थ्य उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि मार्गों का विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सुविधाएं, भीड़ प्रबंधन, खाद्य सामग्री की व्यवस्थाएं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता प्रबंधन आदि की समावेशी एसओपी शीघ्र जारी की जाए। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को पूरी यात्रा का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, सेप्टिक मैनेजमेंट और सेनिटेशन मैनेजमेंट प्लान बनाने के भी निर्देश दिए ताकि यात्रा में भागीदारी करने वाले लोगों को सुविधा मिले तथा पर्यावरण को किसी भी तरह की क्षति भी ना पहुंचे। बैठक में एपीसीसीएफ कपिल लाल, सचिव विनोद कुमार सुमन, धीराज सिंह गर्ब्याल, सी. रविशंकर एवं अपर सचिव विनीत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्वान के कॉप्स होंगे आधुनिक

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल पर जिले में प्रथम बार जनपद के सभी कॉप्स (ष्टश्वद्बद्बश्ठ स्द्दह्1द्बष्द्ग क्क्षद्बठ्ठह्लह्य) को आधुनिक और हाईटेक बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक कॉप्स को कंप्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए।इस अवसर पर चकराता, त्यूनी, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर, डोईवाला, ऋषिकेश में स्थापित काप्स को कम्प्यूटर प्रिंटर उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कॉप्स को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करना आवश्यक है, ताकि आमजन को शासन-प्रशासन से जुड़ी सेवाओं के लिए असुविधा न हो और उन्हें समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।

पीएम व सीएम को ज्ञापन भेज लगाई टीईटी आदेश को निरस्त करने की गुहार

नई टिहरी। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ टिहरी ने सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर टीईटी आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई है। संगठन के जिलाध्यक्ष अध्यक्ष शेर सिंह पंवार, महामंत्री उम्मेद नेगी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में शिक्षकों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने गत एक सितंबर को शिक्षक व शिक्षिकाओं के लिए सेवा में बने रहने व पदोन्नति के लिए 55 वर्ष तक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण का आदेश दिया हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के 15 हजार से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रभावित हो रहे हैं। इस आदेश से शिक्षक तनाव में है। एनसीटीई ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2010 में टीईटी प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण की अनिवार्यता का प्राविधान रखा था। उक्त प्रक्रिया गतिमान है। वर्तमान में टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए 40 वर्ष की आयु निर्धारित है जबकि उच्च न्यायालय ने 55 वर्ष तक के सभी शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करने के आदेश दिए हैं। यह तार्किक एवं न्यायसंगत नहीं है। शिक्षक स्कूलों में पठन- पाठन के साथ कई अन्य विभागीय कार्यों का संपादन भी करते हैं। अधिक उम्र के शिक्षक दो वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना असंभव है। शिक्षकों के संरक्षण एवं भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षकों के सेवा में बने रहने व पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार व एनसीटीई से शिक्षकों को टीईटी पात्रता परीक्षा से मुक्त रखने की मांग की है। इस मौके पर संगठन के प्रदेश महामंत्री जगवीर खरोला, संरक्षक राकेश डोभाल, सुधा उनियाल, प्रकाशी सेमवाल, सविता बडोनी, उर्मिला शाह, अंजू बाला, श्याम लाल आर्य, कुलवीर चौहान, चमन वर्मा, मनोहर चमोली, महेश्वर सेमवाल, प्रमोद नेगी, राजेंद्र कठैत, शूरवीर सिंह टम्टा आदि मौजूद थे।

वॉलंटियर फायर फाइटर्स सम्मानित, प्रयासों की हुई सराहना

अल्मोड़ा। वन चेतना केंद्र, अल्मोड़ा में हंस फाउंडेशन की वन अग्निशमन एवं रोकथाम परियोजना के अंतर्गत वॉलंटियर फायर फाइटर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न गांवों से पहुंचे स्वयंसेवी फायर फाइटर्स को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रभागीय वनाधिकारी (सिविल सोयम) अल्मोड़ा प्रदीप धौलाखंडी और प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह ने स्वयंसेवियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ग्राम स्तर पर सामूहिक सहभागिता को और मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि सामुदायिक जागरूकता, प्रशिक्षण और आपसी समन्वय से आग की घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने वन विभाग को सहयोग देने का भी आह्वान किया। एसडीआरएफ से पंकज डंगवाल ने स्वयंसेवियों को वनाग्नि से बचाव और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। उन्होंने सतर्कता, प्राथमिक सुरक्षा तकनीकों और त्वरित प्रतिक्रिया की अहमियत पर प्रकाश डाला। इस दौरान परियोजना प्रबंधक नागेंद्र तंगवान ने परियोजना की रूपरेखा और उद्देश्यों को साझा किया, जबकि संचालन परियोजना के राजनीश रावत ने किया। स्वयंसेवी फायर फाइटर्स ने भी अपने अनुभव साझा किए और कहा कि स्थानीय स्तर पर उनकी तत्परता और सहयोग जंगलों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और मानव जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वक्ताओं ने माना कि इस तरह के सम्मान समारोहों से स्वयंसेवियों का मनोबल बढ़ता है और अन्य युवाओं को भी वन संरक्षण कार्यों से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। समारोह के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों और स्वयंसेवियों का आभार व्यक्त किया।

यूकेएसएसएससी पेपर लीक से नाराज सैकड़ों युवाओं की भीड़ सड़कों पर उतरी

पिथौरागढ़। यूकेएस एसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर सेंटर से बाहर भेजने के मामले में नाराज सैकड़ों युवाओं की भीड़ बृहस्पतिवार को सड़कों पर उतरी। युवाओं ने पेपर चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए नगर में जुलूस निकालते हुए सरकार, सीएम और आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सीएम और सरकार सशक्त नकल विरोधी कानून बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन प्रदेश में हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक होने से हमारा भविष्य बर्बाद हो गया है। युवाओं ने कहा कि सड़कों पर उतरना हमारा शौक नहीं मजबूरी बन गया है। जिले भर के युवाओं ने नगर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए कलक्ट्रेट तक सरकार और चयन आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। इसके बाद युवा कलक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। युवाओं ने कहा कि प्रदेश में नकल विरोधी कानून बनाकर वाहवाही लूटी गई। इस कानून को दरकिनार कर नकल माफिया हर बार पेपर लीक कर हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। हमारे परिजन अभावों में हमें पढ़ा रहे हैं लेकिन पेपर बाहर आने से हमारी मेहनत बेकार हो रही है। इसके बाद भी सीएम धामी, भाजपा नेता और आयोग के अधिकारी पेपर के सिर्फ तीन पन्ने लीक होने की बात कर हमें धोखा दे रहे हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि सिर्फ आधे नंबर से भी कई युवा भर्ती में सफल होने से रह जाते हैं। इससे साफ है कि यह भर्ती सिर्फ नेताओं और आयोग के चहेतों के लिए कराई गई है। युवाओं ने आयोग के हर कर्मचारी को बदलकर अब तक हुए सभी पेपर बाहर आने के मामलों की सीबीआई जांच की मांग की। कहा कि यदि सरकार और सीएम ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच के आदेश जारी नहीं किए तो प्रदेश भर में युवा उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। पेपर लीक मामले में छात्र-छात्राओं, बेरोजगार युवाओं और जनप्रतिनिधियों ने नगर में प्रदर्शन किया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक
देवेन्द्र जौहरी द्वारा
साप्ताहिक समाचार पत्र
''गुरुकृपा दर्पण'' को
रूद्र प्रिंटिग प्रेस, ई-34,
ओल्ड इड्रस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार
(उत्तराखण्ड) से मुद्रित एवं
एस-3, अशोक विहार कालोनी,
कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
से प्रकाशित।
सम्पादकः **देवेन्द्र जौहरी**
मो. - 9997331129
E-mail :
gurukripadarpan@gmail.com